

an>

Title: Need for delimitation of boundaries of various districts of Delhi.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। नगर निगम की दृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आता है। **â€(लवधान)** अध्यक्ष महोदया, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि हम कितने दर्द में हैं, लेकिन आप ही हमारी संरक्षक हैं, इसलिए मैं इसमें आपकी मदद जरूर चाहुंगा।

अध्यक्ष महोदया, नगर निगम की दृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आता है।... (लवधान) बाकी 20 प्रतिशत हिस्सा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में आता है। होता यह है कि मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र में दो मेयर, पांच डीएम, चार डीसीपी एवं अन्य अलग-अलग संस्थाओं से सम्पर्क रखना पड़ता है। सम्पर्क रखने में मैं कामयाब होता हुं, परन्तु उनके अपने सम्पर्क नहीं हो पाते हैं। उनके आपसी कम्यूनिकेशन ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें पिछले 28 वंशों से एरिया एंथराइज हो गया, लेकिन वहां पानी अब तक नहीं पहुंचा, क्योंकि एनओसी देने वाला विभाग अलग है, खोदने वाला विभाग अलग है, ढकने वाला विभाग अलग है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। यह तालमेल इसलिए नहीं है कि चुनावी क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। मुझे लगता है कि सभी सांसदों के साथ ऐसा होता होगा। इसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है। जैसा माननीय भर्तृहरि महताब जी ने टाइम जोन के बारे में बताया था कि टाइम जोन अलग होने की वजह से खर्च कितने बिलियन डालर ज्यादा होता है, उसी तरह से प्रशासनिक क्षेत्र और चुनावी क्षेत्र में तालमेल न होने की वजह से बहुत ज्यादा खर्च होता है, सांसद के कार्यालय का भी होता है, लोगों का भी होता है और सरकार का भी होता है।

इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें तालमेल बैठाने के लिए चुनावी क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र एक ही होना चाहिए, ताकि मेहनत बचे, खर्च बचे। खासकर दिल्ली में दिक्कत यह है कि कल बरसात हुई थी और ऐसा तालमेल न होने की वजह से सब जगह पानी भर गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी नाकामयाब है कि तालमेल बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुरंत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मैं यह भी मांग करना चाहता हुं। ... (लवधान)

HON. SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Lakhan Lal Sahu,

Shri Nishikant Dubey and

Dr. Virendra Kumar are permitted to associate with the issue raised by Shri Maheish Girri.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, क्या इस तरह से स्टेट के बारे में इश्यू रेज कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष : उनको डिजिटलमिडेशन की मांग करनी थी, तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी।

â€(लवधान)